रालोद के दबाव में झुकी सरकार

- किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान न होने पर फिर होगा आंदोलन : जयंत चौधरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को तुरंत चालू करने के लिए सरकार और मिल मालिकों के बीच समझौता होते ही उसका श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि गन्ना किसानों के मसले पर उसका दबाव एवं आंदोलन रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार की तरफ से चीनी मिलों को तुरंत चालू कराने का एलान उसकी ही लड़ाई का नतीजा है।

रालोद ने रविवार को जारी एक बयान में दल के महासचिव एवं सांसद जयंत चौधरी के हवाले से कहा कि गन्ना किसानों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में उसके चक्का जाम और लखनऊ में विधानसभा और गन्ना आयुक्त का घेराव आखिर काम आया। किसानों ने रालोद का पूरा साथ दिया। प्रदेश की सपा सरकार को झुकना पड़ा। नतीजा यह रहा कि सरकार को चीनी मिलों को तत्काल चालू कराने का एलान करना पड़ा। हालांकि, उसके बाद भी गन्ना किसानों के लिए रालोद का संघर्ष जारी रहेगा। जयंत चौधरी ने कहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के चार सौ करोड़ रुपये बकाया है। मिलों को चलवाने के बाद प्रदेश सरकार किसानों को उनके बकाये का शीघ्र भुगतान नहीं करती तो रालोद फिर आंदोलन की राह अख्तियार करेगा। इसके साथ ही गन्ना किसानों व चीनी मिल मालिकों की दिक्कतों को दूर करने के लिए रालोद केंद्र पर भी अपना दबाव बनाए रखेगा।

गन्ना किसानों के लिए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी

- उत्पादन मूल्य में वृद्धि के हिसाब से हो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
- डब्ल्यूटीओ में पीस क्लॉज ध्वस्त कर देगा भारत की खाद्य सुरक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कई राज्यों में चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन से लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में 'पीस क्लॉज' पर हो रही वार्ता के बीच भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सतर्क किया है। रविवार को एक पत्र लिखकर राजनाथ ने आरोप लगाया है कि केंद्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसे तत्काल दुरुस्त किया जाना चाहिए। वहीं, पीस क्लॉज को राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताते हुए उन्होंने समर्थन से आगाह किया है। गन्ना किसानों का असंतोष उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उफान पर है। राजनाथ ने इसकी याद दिलाते हुए पीएम से कहा कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का दावा तो कर रही है लेकिन यह वृद्धि उत्पादन मूल्य में बढ़ोतरी को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने पत्र में पिछले तीन वर्षों में हुई बढ़ोतरी का आंकड़ा भी दिया। उत्तर प्रदेश को कठघरे में कड़ा करते हुए उन्होंने शिकायत की कि वहां गन्ना किसानों को बकाया 2,300 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। लखीमपुर खीरी में एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। स्थिति को तत्काल सुलझाना चाहिए वरना हालात खराब हो सकते हैं। वहीं, पीस क्लॉज का विरोध करते हुए राजनाथ ने आगाह किया कि अगर सरकार डब्ल्यूटीओ में यह प्रस्ताव देती है तो खाद्य सुरक्षा कानून खतरे में घिर सकता है। लिहाजा पीस क्लॉज की बजाय 'फूड सिक्योरिटी बॉक्स' पर सहमति बनाई जानी चाहिए।

गन्ने से जुड़ी दिक्कतों को निपटाने के लिए केंद्र ने बीते दिनों मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। रालोद प्रमुख एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजित सिंह भी उसके सदस्य है। समूह में जरूरी मसलों पर वह रालोद की राय को उसके सामने रखेंगे।

Dainik Jagaran

2/12/13